भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 211

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

यूपीआई के लेन-देन में धोखाधड़ी

211. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश में माह-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन किए गए और यूपीआई लेन-देन में धोखाधड़ी की कितनी घटनाएं रिपोर्ट की गई;

(ख) सरकार द्वारा यूपीआई के सुरक्षित लेन-देन और लेन-देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या अपेक्स बैंक का विचार भुगतान के लिए यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने का है और यदि हां, तो सरकार द्वारा भुगतान में सुगमता के लिए वित्तीय क्षेत्र के प्रयोक्ताओं हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में भौगोलिक स्थान कैप्चर नहीं होता है। तथापि, विगत दो वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश में हुए यूपीआई लेनदेन अनुबंध-I में दिए गए हैं।

आरबीआई ने मार्च 2020 से वेब-आधारित भुगतान संबंधी धोखाधड़ी रिपोर्टिंग टूल, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) आरंभ किया है। सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) से भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों को उक्त सीपीएफआईआर में रिपोर्ट करने की अपेक्षा की गई है। विगत दो वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई यूपीआई घरेलू भुगतान धोखाधड़ियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख): यूपीआई लेनदेन संबंधी धोखाधड़ियों सहित भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकार, आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर कई पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस की बाइंडिंग करना, पिन के माध्यम से द्वि-स्तरीय अधिप्रमाणन, दैनिक लेनदेन सीमा, यूज़ केस के संबंध में सीमाएं और प्रतिबंध आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई सभी बैंकों को धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए समाधान उपलब्ध कराता है ताकि वे

एआई/एमएल आधारित मॉडल का उपयोग करके धोखाधड़ी को कम करने के लिए लेनदेन के संबंध में अलर्ट करने और उसे निरस्त करने में सक्षम हो सकें। आरबीआई और बैंक 'साइबर-अपराध' निवारण के संबंध में शॉर्ट एसएमएस, रेडियो कैम्पेन और प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं।

नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ियों सहित किसी साइबर संबंधी घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक बैंकों की आधिकारिक ग्राहक सेवा वेबसाइट पर या शाखाओं में भी वित्तीय धोखाधड़ी को रिपोर्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने डिजिटल आसूचना प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और संचार साथी पोर्टल (https://sancharsaathi.gov.in) पर 'चक्षु' सुविधा आरंभ की है। 'चक्षु' नागरिकों को फोन कॉल, एसएमएस या व्हाट्सऐप के माध्यम से केवाईसी की एक्सपायरी या बैंक खाते को अद्यतन करने आदि जैसी धोखाधड़ियों के इरादे से संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

(ग): आरबीआई के पेमेंट विजन डॉक्युमेंट 2025 में यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच के विस्तार को 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' स्तंभ के अंतर्गत मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में दर्शाया है।

इस संबंध में आरबीआई वर्तमान में यूपीआई की पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न संबंधित हितधारकों के साथ निम्नलिखित तरीकों से सहयोग कर रहा है:-

i. पारस्परिक आधार पर व्यक्तिगत प्रेषण के लिए यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणाली (एफपीएस) के साथ इंटरलिंक करना।

ii. विदेशों में व्यापारिक स्थानों पर क्यूआर कोड्स के माध्यम से यूपीआई ऐप्स की स्वीकार्यता और उसके उलट स्थिति की स्वीकार्यता।

iii. अन्य देशों में यूपीआई जैसी अवसंरचना का अभिनियोजन।

******

अनुबंध I

माह	वित्तीय वर्ष					
	2022-23		2023-24		2024-25*	
	मात्रा (करोड़)	मूल्य (लाख करोड़)	मात्रा (करोड़)	मूल्य (लाख करोड़)	मात्रा (करोड़)	मूल्य (लाख करोड़)
अप्रैल	558.44	9.84	886.33	14.16	1,330.40	19.64
मई	594.63	10.40	941.52	14.89	1,403.58	20.45
जून	586.29	10.14	933.51	14.75	1,388.51	20.07
जुलाई	628.93	10.63	996.43	15.34	1,443.56	20.64
अगस्त	658.19	10.73	1058.60	15.77	1,496.30	20.61
सितंबर	678.08	11.16	1055.57	15.79	1,504.17	20.64
अक्टूबर	730.54	12.12	1140.88	17.16		
नवंबर	730.94	11.91	1123.53	17.40		
दिसंबर	782.89	12.82	1202.02	18.23		
जनवरी	803.86	12.99	1220.30	18.41		
फ़रवरी	753.48	12.36	1210.27	18.28		
मार्च	865.16	14.05	1344.00	19.78		
कुल	**8371.43**	**139.15**	**13112.96**	**199.96**	**8,566.52**	**122.05**

**सितम्बर, 2024 तक*

अनुबंध - II

यूपीआई घरेलू भुगतान धोखाधड़ी		
वित्तीय वर्ष	**घटनाओं की संख्या (लाख में)**	**अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये)**
वित्तीय वर्ष 2022-23	7.25	573
वित्तीय वर्ष 2023-24	13.42	1087
वित्तीय वर्ष 2024-25*	6.32	485

**सितम्बर, 2024 तक*